

नौसेना के स्वदेशीकरण का प्रयास

प्रलम्बिस् के लयि:

रकषा कषेत्र से संबधति पहलें ।

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिँ और हसतकषेप, प्रौद्योगकिी का स्वदेशीकरण, रकषा के स्वदेशीकरण का महत्त्व तथा संबधति चुनौतयिँ ।

चर्चा में क्यौं?

रकषा आयात में कटौती एवं घरेलू वनरिमाण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास के अनुरूप नौसेना वशिष रूप से हथयिरों एवं वमिनन से संबधति वस्तुओं में स्वदेशीकरण के प्रयासों को तीव्र कर रही है ।

- **युक्रेन में चल रहे युद्ध** एवं रूसी हथयिरों तथा उपकरणों पर भारतीय सेना की बड़े पैमाने पर नरिभरता के कारण स्वदेशीकरण के प्रयासों में और तेज़ी आई है ।
- इससे पहले रकषा मंत्रालय (MoD) ने 101 वस्तुओं की '**तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण**' सूची जारी की है, जसिमें प्रमुख उपकरण/प्लेटफॉर्म शामिल हैं ।

स्वदेशीकरण हेतु नौसेना के प्रयास:

- **भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015-2030:**
 - वर्ष 2014 में नौसेना ने उपकरण एवं हथयिर प्रणाली के स्वदेशी वकिस को सकषम करने के लयि भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (INIP) 2015-2030 को प्रख्यापति कयि था ।
 - अब तक नौसेना ने इस योजना के तहत लगभग 3400 वस्तुओं का स्वदेशीकरण कयि है, जसिमें 2000 से अधिक मशीनरी और बजिली पुरजे, 1000 से अधिक वमिनन पुरजे और 250 से अधिक हथयिर शामिल हैं ।
- **नौसेना उड्डयन स्वदेशीकरण रोडमैप 2019-22:**
 - मौजूदा नौसेना उड्डयन स्वदेशीकरण रोडमैप (NAIR) 2019-22 भी संशोधन के अधीन है ।
 - संशोधति NAIR 2022-27 में सभी तेज़ गति वाले वमिन अनविर्य पुरजे और उच्च लागत वाले स्वदेशी मरमत उपकरणों को शामिल कयि जा रहा है ।
 - फाइट कंपोनेंट (जो कसिवयं हथयिर हैं) पर वशिष ध्यान दयिा जाता है, क्यौंकफ्लोट एवं मूव कंपोनेंट्स की तुलना में इस कषेत्र में अभी और अधिक कार्य कयिा जाना है ।
 - फ्लोट कंपोनेंट के रूप में जहाज़ होता है, मूव कंपोनेंट्स में 'प्रणोदन' शामिल होता है तथा फाइट कंपोनेंट में हथयिर और सेंसर शामिल होते हैं ।
- **स्वदेशीकरण समतियिँ:**
 - नौसेना वमिननों के पुरजों के स्वदेशीकरण की देखभाल के लयि चार आंतरकि स्वदेशीकरण समतियिँ का गठन कयिा गया है ।
- **नौसेना संपर्क प्रकोषट:**
 - इसके अलावा वभिन्न स्थानों पर स्थति नौसेना संपर्क प्रकोषटों (NLCs) को 'स्वदेशीकरण प्रकोषट' के रूप में नामति कयिा गया है ।
 - वर्तमान में 41 जहाज़ और पनडुबबयिँ नरिमाणाधीन हैं जसिसे से 39 भारत के शपियार्ड में बनाए जा रहे हैं, जबक सैद्धांतकि रूप से भारत में 47 जहाज़ों के नरिमाण हेतु रकषा मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त है ।
 - वर्ष 2014 से आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity- AoN) का 78%, और अनुबंध के 68% मूल्य के आधार पर भारतीय वकिरेताओं को प्रदान कयि गए हैं ।
 - AoN ने टेंडर प्रक्रयिा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दयिा है ।
- **DRDO के साथ सहयोग:**
 - नौसेना, **रकषा अनुसंधान और वकिस संगठन** (DRDO) तथा उद्योग के साथ वकिस की समयसीमा में कटौती हेतु कार्य कर रही है ।
 - कुछ फोकस कषेत्रों में स्वदेशी डिज़ाइन और वकिसति एंटी-सबमरीन हथयिर, सेंसर, सैटकॉम, इलेक्ट्रॉनकि युद्ध उपकरण, एंटी-शिप मसिाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मसिाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सॉफ्टवेयर, रेडयिो, नेटवर्क

एनक्रिप्शन डेवाइस लकि ॥ संचार प्रणाली, पनडुबयों हेतु मुख्य बैटरी, सोनार प्रणाली, मसिइलों और टॉरपीडो के घटक आदि शामिल हैं।

■ नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO):

- इसे अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना क्षमता विकास तंत्र के साथ शिक्षा और उद्योग के लिये एक लचीला व सुलभ इंटरफेस प्रदान करता है।
- पछिले दो वर्षों में नौसेना कर्मियों द्वारा 36 बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हेतु आवेदन दायर किये गए हैं।
 - NIIO के नरिमाण और 12 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बाद से हर महीने दो से अधिक आईपीआर आवेदन दायर किये जा चुके हैं।

■ नौसेना परियोजना प्रबंधन टीमों के तहत यूजर इनपुट:

- नौसेना ने अब डीआरडीओ के क्लस्टर मुख्यालय में नौसेना परियोजना प्रबंधन टीमों के माध्यम से यूजर इनपुटका उपयोग किया है और ऐसे दो क्लस्टर पहले से ही चालू हैं।
- ये भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमता को विकसित करने हेतु चल रही 15 भविष्य की प्रौद्योगिकियों और 100 से अधिक DRDO परियोजनाओं के लिये प्रत्येक चरण में यूजर इनपुट प्रदान करने हेतु DRDO प्रयोगशालाओं तथा उनके विकास सह-उत्पादन भागीदारों (Development cum Production Partners- DcPP) के साथ इंटरफेस (Interface) कर चुके हैं।

■ मेक I और मेक II:

- खरीद प्रक्रिया के विभिन्न घरेलू विकास मार्गों के तहत नौसेना के 20 से अधिक **मेक I और मेक II** पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
 - पूंजी अधिग्रहण की '**मेक**' श्रेणी **मेक इन इंडिया पहल** की आधारशिला है जो सार्वजनिक और नज्जी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्वदेशी क्षमताओं का नरिमाण करना चाहती है।
 - '**मेक-आई**' सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को संदर्भित करता है, जबकि '**मेक-द्वितीय**' उद्योग-वित्तपोषित कार्यक्रमों को कवर करता है।
 - '**मेक-I**' भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लाइट टैंक और संचार उपकरण जैसे बड़े-प्लेटफॉर्मों के विकास में शामिल है।
 - **मेक-II** श्रेणी में सैन्य हार्डवेयर का प्रोटोटाइप विकास या आयात प्रतिस्थापन के लिये इसका उन्नयन शामिल है जिसके लिये सरकारी धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

रक्षा का स्वदेशीकरण:

■ परिचय:

- स्वदेशीकरण आत्मनिर्भरता और आयात के बोझ को कम करने के दोहरे उद्देश्य के लिये देश के भीतर किसी भी रक्षा उपकरण के विकास और उत्पादन की क्षमता है।
- रक्षा नरिमाण में आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
 - **रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs)** और नज्जी संगठन रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है तथा सशस्त्र बलों की रक्षा खरीद पर अगले पाँच वर्षों में लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है।

■ संबंधित पहल:

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई।
- **आयुध नरिमाणी बोर्डों का नगिमीकरण**।
- **डफिंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज**।
- **सृजन पोर्टल**: स्वदेशीकरण हेतु वस्तुओं को खरीदने के लिये विक्रेताओं तक पहुँच प्रदान करना।

स्रोत: द हट्टू